

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या : 4382  
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/ चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**‘उड़ान’ योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क**

**4382. श्री गौरव गोगोई:**

**श्री बैन्नी बेहनन:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024-25 में उड़ान योजना के तहत कितने नए क्षेत्रीय विमानपत्तन और हवाई मार्ग चालू किए गए हैं;

(ख) क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए विमान कंपनियों और विमानपत्तन संचालकों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) ‘उड़ान’ मार्गों की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं और सरकार द्वारा उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)**

(क) और (ख): वर्ष 2024-25 के दौरान, क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत 04 हवाईअड्डों और 02 हेलीपोर्टों को प्रचालनरत किया गया है। वर्ष 2024-25 (आज की तारीख तक) के दौरान 66 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया गया है।

उड़ान योजना के तहत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतों के माध्यम से चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों (एसएओ) को सहायता देकर, ताकि क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन की लागत को कम किया जा सके और इस अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर निधि या वीजीएफ) सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क की वहीनीयता को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत अब तक एयरलाइनों को 4023 करोड़ रुपये की वीजीएफ सहायता प्रदान की गई है।

(ग): उड़ान एक बाजार आधारित सतत योजना है जिसमें और अधिक गंतव्यों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया के दौर आयोजित किए जाते हैं। एयरलाइनों को मार्गों और व्यवहार्यता के अपने स्वयं के आकलन के आधार पर बोली प्रक्रिया के दौर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उड़ान योजना के अंतर्गत मार्गों की दीर्घकालिक संधारणीयता में सुधार करने हेतु, निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया जाता है:

1. अपने-अपने क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए, उनसे उच्च क्षमता वाले हवाईअड्डों जिन्हें विकसित और प्रचालित किया जा सकता है, की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय ज्ञान और उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाते हुए विमानन अवसंरचना के विस्तार के लिए अधिक दक्ष और रणनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

2. अवार्ड किए गए मार्गों की तुलना में पहले से ही परिचालनरत मार्गों की संख्या बढ़ाने के लिए, एयरलाइनों को समय पर परिचालन के लिए मार्ग के आवंटन से पहले ही व्यावसायिक योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कार्यान्वयन एजेंसी उन प्राथमिकता वाले हवाईअड्डों की सूची भी प्रकाशित कर रही है जो तैयार हैं अथवा 6 महीने में तैयार हो जाएँगे। इसके साथ-साथ, एयरलाइन विफलता जैसे विभिन्न कारणों से पिछले बोली दौर में बंद किए गए पात्र मार्गों की भी बाद के दौर में फिर से बोली लगाई गई, उन्हें अवार्ड और चालू किया गया। यह एक विकसनशील प्रक्रिया है।

\*\*\*\*\*